



ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। उन्होंने देशनोक के पलाना गांव की रोही में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री का साफा पहनाकर स्वागत किया।

अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी-मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा कि अब बात सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की होगी

बीकानेर, 22 मई (कास)। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहली बार बीकानेर आए। जिला मुख्यालय से 22 किमी. दूर देशनोक के पलाना गांव की रोही में हुई विशाल जनसभा में मोदी करीब 40 मिनट बोले। उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की हर हरकत का करारी जवाब दिया जायेगा। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दो टूक संदेश देते हुए कहा कि अब हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और ये कीमत पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चुकायेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकवादियों ने धर्म पुछकर हमारी बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया था। वो गोलियां पहलगांम में चली थीं, लेकिन उन गोलियों से 140 करोड़ देशवासियों का सीना छलनी हुआ था। इसके बाद हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे और उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा देंगे। उन्होंने कहा कि देशवासियों के आशीर्वाद से और देश की सेना के शौर्य से हम सब उस प्रण पर खरे उतरे

■ जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी भुजिया का स्वाद और बीकानेरी रसगुल्ले की मिठास विश्व भर में पहचान बनायेगी।

■ पलाना की सभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि पांच साल पहले बालाकोट के बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में हुई थी। इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहली सभा यहाँ हो रही है। राजस्थान की वीरभूमि के तप से ऐसा संयोग बना है।

हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और तीनों सेनाओं ने मिलकर ऐसा चक्रव्यूह रचा कि पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी का दिमाग ठंडा रहता है लेकिन लहू गर्म रहता है और अब तो मोदी की नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है। पाकिस्तान के साथ न तो व्यापार होगा, न ही बातचीत होगी। यदि बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को

वापस लेने की। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान ने अगर आतंकियों को एक्सपोर्ट करना जारी रखा तो उसको पाई-पाई के लिए मोहताज होना होगा। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। एटम बम की गीदड़ भभकियों से भारत डरने वाला नहीं है। मोदी ने कहा कि जब मैं दिल्ली से यहां आया तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। यहां से कुछ ही दूर सीमापार पाकिस्तान का रहीमयार

खान एयरबेस अगले कई दिनों के लिए बंद हो चुका है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयरबेस को तहस-नहस कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए केन्द्र और राज्य की डबल इंजन सरकार तेजी से काम कर रही है। राजस्थान की रीफाइनी का काम भी अंतिम चरण में है। अमृतसर-जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे राजस्थान में औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग-अलग क्षेत्रों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार द्वारा जारी नई औद्योगिक नीतियों का लाभ बीकानेर को भी मिलेगा। बीकानेरी रसगुल्लों की मिठास विश्वभर में अपनी पहचान और बढ़ाएंगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पांच साल पहले जब बालाकोट में देश ने एयर स्ट्राइक की थी, उसके बाद मेरी पहली जनसभा राजस्थान में ही हुई (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एक बार फिर विदेश मंत्री जयशंकर ने ट्रम्प के मध्यस्थता के दावे को केवल कल्पना बताया

ट्रम्प की नाराज़गी सहने के लिये भारत को तैयार रहना पड़ेगा

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 मई। "अमेरिका केवल अमेरिका तक ही सीमित था।" विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने "ऑपरेशन सिंदूर" के दौरान भारत-पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता में अमेरिका की मध्यस्थता पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह टिप्पणी की।

10 मई को युद्धविराम घोषित होने के बाद से अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एक फोन कॉल के जरिए दोनों देशों को व्यापार का प्रस्ताव देकर यह शांति स्थापित करवाई थी।

जो कोई भी भारत और पाकिस्तान के बीच की संवेदनशीलता और विवाद की पुष्टभूमि से जरा भी परिचित है, वह जानता है कि ट्रंप का यह दावा कितना अतार्किक और हास्यास्पद है। यही कारण है कि भारत, विशेष रूप से विदेश मंत्री एस. जयशंकर, लगातार यह स्पष्ट कर रहे हैं कि युद्धविराम केवल दोनों देशों के बीच आपसी सहमति से हुआ था। अमेरिकी राष्ट्रपति के डील मेकर का क्रेडिट लेने की कोशिश को खारिज करने के निस्संदेह अलग नतीजे होंगे। इससे

■ ट्रम्प के दंभ भरे दावों को अब विश्व ज्यादा गंभीरता से नहीं ले रहा, चाहे एक ही दिन में यूक्रेन युद्ध समाप्त कराने की घोषणा हो, या रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी हो, या यमन के हूती को अपनी भारी नौ सेना से डराने का प्रयास हो, या ईरान के अयतुल्ला खमेनी को चेतावनी देने की कोशिश हो।

■ अतः बार-बार भारत-पाक के बीच अपनी मध्यस्थता से सीज़फायर कराने का दावा, ट्रम्प की मजबूरी बन गया है।

■ पर, भारत के विदेश मंत्री द्वारा ट्रम्प को इस "सीज़फायर" के लिए कोई भी श्रेय नहीं देना, ट्रम्प प्रशासन के लिए पचाना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस खीज की गाज, भारत पर गिर सकती है।

पहले भी ट्रंप ने दावा किया था कि यदि वे चुने जाते हैं तो यूक्रेन युद्ध को एक दिन में समाप्त कर सकते हैं-जो पूरी तरह से एक कपोल कल्पना साबित हुई। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने में असफल रहने के बावजूद, ट्रंप लगातार खुद को रूस-यूक्रेन शांति प्रक्रिया का नायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बार-बार यह स्पष्ट कर चुके हैं कि

दावा किया कि यूक्रेन युद्ध केवल तब खत्म होगा, जब वे स्वयं पुतिन से बात करेंगे। उनके कैबिनेट सदस्य बार-बार उनकी "शानदार शक्तिशाली" की तारीफ करते रहे, उनका मत था कि ट्रंप का करिश्माई व्यक्तिगत पुतिन को शांति की ओर ले जाएगा।

हालांकि, पुतिन से दो घंटे लंबी टेलीफोन बातचीत के बाद भी शांति की कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिखी। उल्टा, रूस ने अपने हमले और तेज कर दिए, जिससे यूक्रेनी जनता को और अधिक नुकसान उठाना पड़ा।

ट्रंप की इन लगातार कूटनीतिक विफलताओं के बीच, अमेरिका इतना व्यग्र है कि "सफलता" के मामूली से संकेत तक को लपक लेना चाहता है। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने अमेरिका की सबसे शक्तिशाली नौसेना पर हमला किया, जिससे अमेरिकी प्रतिष्ठा को गहरा अघात पहुंचा। इसके बाद, ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई ने भी अमेरिका और ट्रंप को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने ईरान पर सीधा हमला किया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विवाह के तीन माह बाद ही आत्महत्या, अभियुक्त पति को आजीवन कारावास

जयपुर, 22 मई। महिला उल्पीडन मामलों की विशेष अदालत ने दहेज प्रताड़ना से तंग आकर विवाह के तीन माह बाद ही विवाहिता के आत्महत्या करने के मामले में उसके पति विकास शर्मा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, अदालत ने अभियुक्त पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन

■ मृतका के भाई ने बयान दिया कि उसकी बहन ने बताया था कि उसका पति व ससुराल वाले दहेज के लिए मारपीट करते हैं।

अधिकारी आशुतोष कुमावत ने अपने आदेश में कहा कि एक लड़की के लिए उसका विवाह जीवन का एक महत्वपूर्ण पल होता है, जहां वह अपने पिता के संरक्षण से दूर सुंदर भविष्य का सपना देखते हुए अपने पति के साथ विदा होती है। उस समय लड़की के मन में यह विश्वास होता है कि उसका पति, उसके

सतपाल मलिक के खिलाफ चार्जशीट फाइल की सीबीआई ने

सतपाल मलिक, जम्मू-कश्मीर के गवर्नर थे तथा उस दौरान उन पर किरू में हाइड्रो पावर प्रोजैक्ट का ठेका देने का आरोप लगाया गया था

- डॉ. सतीश मिश्रा -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 22 मई। प्रतिशोध का मामला प्रतीत होने वाली एक कार्यवाही के अन्तर्गत, सी बी आई ने जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक एवं पांच अन्य के खिलाफ चार्जशीट पेश की है। यह प्रकरण कोरू हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के लिए 2200 करोड़ रु. के 'सिविल वर्क्स' का ठेका दिये जाने में हुए कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है।

अधिकारियों ने आज कहा कि एंजेंसी ने 3 साल की जांच पड़ताल के बाद, अपने निष्कर्ष एक विशेष अदालत में पेश कर दिये हैं। इस प्रकरण मलिक एवं पांच अन्य लोग आरोपी बनाये गये हैं।

आज 'एक्स' पर डाली गई पोस्ट में मलिक ने कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा किसी से बात करने की स्थिति में नहीं हैं। पूर्व राज्यपाल ने कहा कि उनके

■ सीबीआई ने इस आरोप की तीन साल तफतीश करके यह चार्जशीट दाखिल की है।

■ सतपाल मलिक ने इस घटनाक्रम के बारे में कहा कि वे किसान पुत्र हैं तथा सरकार उन्हें डराना व दबाना चाहती है, पर, वे झुकेंगे नहीं।

■ सतपाल मलिक ने एक्स पर यह भी कहा कि वे अस्पताल में भर्ती हैं तथा अस्वस्थ हैं। अतः उन लोगों से बात नहीं कर पा रहे, जो उन्हें फोन कर रहे हैं।

पास बहुत से शुभचिन्तकों के कॉल आ रहे हैं, लेकिन वे बात नहीं कर पा रहे हैं। सी बी आई गत वर्ष फरवरी में इस केस के संदर्भ में मलिक एवं अन्य के परिसरों की तलाशी ली थी।

सी बी आई ने 2022 में एफ आई आर दर्ज करने के बाद, एक बयान में कहा था कि यह केस 2019 में कोरू हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर (एच ई पी) प्रोजेक्ट के सिविल वर्क्स का 2200

करोड़ रु. का ठेका एक प्राइवेट कंपनी को दिये जाने में की गई कथित गड़बड़ी से संबंधित है।

मलिक, जो 23 अगस्त, 2018 से 30 अक्टूबर, 2019 तक जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल थे, ने दावा किया था कि उन्हें दो फाइलों पर स्वीकृति देने के लिए 300 करोड़ रु. की रिश्त की पेशकश की गई थी। इनमें से एक फाइल (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को बीस साल की सजा

जयपुर, 22 मई। पाँक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त विजय वर्मा को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी विकास कुमार खंडेलवाल ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने

■ अभियुक्त ने दुष्कर्म का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था।

16 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ जबर्न दुष्कर्म कर उसकी अश्लील फोटो व वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह गंभीर अपराध है और ऐसे अभियुक्त के साथ कोर्ट किसी तरह की नरमी नहीं बरत सकती।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मातादीन शर्मा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने बनीपार्क पुलिस थाने में 22 जून 2022 को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सात प्रतिनिधिमंडल, जिनमें 32 प्रमुख राजनीतिक नेता शामिल हैं, पाकिस्तान की आतंकवादी हमलों में भूमिका को समझाने, विश्व यात्रा पर निकले

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 22 मई। एक अभूतपूर्व राजनीतिक घटनाक्रम में, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के 32 प्रमुख नेताओं के सात प्रतिनिधिमंडलों ने लगभग तीन दर्जन देशों की कूटनीतिक यात्राओं की शुरुआत की है। इन सभी का एक ही उद्देश्य है: भारतीय भूमि पर लंबे समय से चल रही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की नीति के विश्वसनीय प्रमाण प्रस्तुत करना, जिसके कारण निर्दोष पर्यटकों और नागरिकों की जानें गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 11 वर्षों के कार्यकाल में यह पहली बार है जब इतने व्यापक स्तर पर राजनीतिक सहयोग नजर आया है, जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने विपक्षी दलों के साथ एक साझा राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाया है।

ये प्रतिनिधिमंडल लगभग तीन दर्जन देशों का दौरा करेंगे, पाकिस्तान की भूमिका के प्रमाण भी प्रस्तुत करेंगे

दुर्लभ एकता के इस प्रदर्शन के बावजूद भी इस पहल ने देश में राजनीतिक हलचल मचा दी है। सरकार पर आरोप लगे हैं कि उसने उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों के चयन में संबंधित दलों से औपचारिक सलाह-मशविरा नहीं किया। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शशि थरूर और सलमान खुर्शीद को कथित तौर पर पार्टी की औपचारिक सहमति के बिना शामिल किया गया, क्रिकेटर से राजनेता बने तुषमूल सांसद युसुफ पठान के मामले में भी ऐसा ही हुआ। इसने दलों के भीतर अंदरूनी कलह को जन्म दिया है और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हरि देसाई, जो प्रधानमंत्री मोदी की भाजपा

■ पर, एक प्रकार से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की मोदी सरकार की सराहनीय सफलता का मुँह में पूरा स्वाद आता उससे पहले कुछ किरकिरी आ गई, विपक्ष की कुछ पार्टियों की इस शिकायत से कि उनसे पूछा नहीं गया, उनके नेताओं को प्रतिनिधिमंडल में शामिल करने से पहले।

■ इस आंतरिक विवाद का असर देश के कई राज्यों पर पड़ेगा। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में "महायुति" गठबंधन में भी उथल-पुथल हो सकती है। शरद पवार व उनके भतीजे अजित पवार के दोनों धड़े अब एक होने के प्रयास में लगभग सफल हो गये हैं तथा देवेन्द्र फड़नवीस की सरकार को इससे मजबूती मिलेगी।

■ प्रतिनिधिमंडल भेजने की इस नीति से घटनाओं की एक शृंखला शुरू हो गई है, जिसका असर भारत के राजनीतिक घटनाक्रम में काफी समय तक प्रभावी रहेगा।

प्रचारक से लेकर अब तक की राजनीतिक यात्रा पर लंबे समय से नजर रखते आए हैं, ने इस कदम की

आलोचना की। उन्होंने कहा, "ऐसे समय में जब देश को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एकजुट चेहरा दिखाना चाहिए,

प्रधानमंत्री मोदी की यह रणनीति पार्टियों के भीतर आपसी कलह को जन्म दे रही है। एकता के नाम पर इस तरह का

विभाजनकारी कदम निराशाजनक और राजनीतिक रूप से खतरनाक है।" राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस कूटनीतिक मिशन का प्रभाव विदेश नीति से परे भारत की आंतरिक राजनीति पर भी पड़ सकता है। महाराष्ट्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के दोनों धड़े, शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाला पुनः एकजुट होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर यह मेल होता है, तो राज्य की सत्ता-संरचना में बड़ा बदलाव आ सकता है।

यह एकता सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन, जिसका नेतृत्व भाजपा के देवेंद्र फड़नवीस कर रहे हैं, को लाभ पहुंचा सकती है। राज्य भाजपा के सूत्रों के अनुसार, एकजुट राकांपा सरकार को कुछ नीतिगत रियायतों के बदले सशर्त समर्थन दे सकती है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अब तक नहीं हुई है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गलत जानकारी देने पर हाईकोर्ट ने 50 हजार का हर्जाना लगाया

जयपुर, 22 मई। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में गलत तथ्य बताकर याचिका दायर करने को गंभीर माना है। इसके साथ ही, अदालत ने आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर पचास हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। जस्टिस समीर जैन की

■ अदालत ने पुरुषोत्तम दाधीच की पेपर लीक मामले में दायर अपराधिक याचिका खारिज की।

एकलपीठ ने यह आदेश पुरुषोत्तम दाधीच की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि उस पर अपनी प्रेमिका के लिए पन्द्रह लाख रुपए में एसआई भर्ती का प्रश्न पत्र खरीदने का आरोप है। मामले में वह निचली अदालत में संरेख करने भी गया था, लेकिन अदालत ने उसे अपनी कस्टडी में नहीं लिया। मामले में दर्ज एफआईआर में भी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)